B.M.A. College Baheri Darbhanga (LNMU)
B.A (Hons) Part-1 Paper-II Economics

1
21-08-2020

राष्ट्रीय कृषि नीति 2007,

Dr. S.K. Singh
Deptt of Economics

(National Agriculture policy, 2007)

26 नवम्बर, 2007 को राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 को केन्द्र सरकार द्वारा संसद मे प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी सिफारिशों में नयी राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा करने की अनुशंसा की थी। नयी राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 मे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता मे वृद्धि, कृषको की आर्थिक स्थिति में सुधार, कृषि क्षेत्र मे नयी तकनीक का प्रयोग तथा सिंचाई सुविधा का विकास एवं प्रसार के साथ साथ कृषि उत्पादो के निर्यात पर फोकस किया गया है।

(1) इस नीति में कृषि क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने तथा रोजगार जननी के रूप में विकसित किया जाएगा।

(2) कृषि नीति 2007 के अन्तर्गत भूमि सुधारो के अधूरे एजेंडे को लागू करने तथा कृषि योग्य भूमि के गैर कृषि उपयोग में कमी लाई जायेगी।

(3) इस नीति मे किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने तथा किसान परिवारो को गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गयी है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों मे आजीविका के संसाधनो की स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषि इकाइयों को उपयोगी बनाने की पहल करने अथवा एजेंसी सृजित करने पर फोकस किया गया है।

(5) नीति में फसलो को उचित मूल्य तथा किसानो की आय बढ़ाने के लिए व्यापार तन्त्र को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है।

(6) किसान को परिभाषित किया गया है, जिसमें कृषि तथा इससे संबद्ध क्षेत्र मे काम करने वालो को भी सम्मिलित किया गया है।

(7) जेनेटिकली मॉडीफाइड बीजों को बढ़ावा देने के साथ-साथ जैविक खेती को भी महत्व प्रदान किया जाएगा।

(8) नयी राष्ट्रीय कृषि नीति में छोटी जोत वाले किसानो को लाभदायी व्यवसाय देने के लिए ठेके पर खेती तथा किसान कम्पनियां बनाने की बात कही गयी है।

(9) इस नीति मे कृषि साख को सुलभ, सुगम तथा सस्ता बनाने पर बल दिया गया है। इस नीति में किसानों की ऋणग्रस्तता पर सीधे तौर पर कुछ नही कहा गया है। परन्तु यह अवश्य कहा गया है कि कृषको की ऋणग्रस्तता को लेकर सरकार भविष्य मे गतिशील कार्यक्रम शुरू करेगी।

आर्थिक प्रणाली: अभिप्राय एवं परिभाषाएं,

Dr. S.K. Singh
Deptt of Economics

(Economic system: meaning and Definitions)

आर्थिक प्रणाली के संचालन होने से अभिप्राय उस कार्य विधि से होता है जिसके अन्तर्गत किसी पूर्व-निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोचने का निर्णय लेने का और आर्थिक क्रियाएं सम्पन्न कराने का मार्ग निर्धारित किया जाता है। ये सभी आर्थिक क्रियाएं संगठित होकर एक आर्थिक प्रणाली की संरचना करती हैं।

आर्थिक प्रणाली ऐसी संस्थाओं का ढंचा है जिसके द्वारा समाज की समस्त आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। प्रत्येक देश किसी-न-किसी आर्थिक प्रणाली पर आधारित है और आर्थिक प्रणाली की भिन्नता के अनुसार अर्थव्यवस्था का संचालन भी भिन्न भिन्न है, किन्तु यह एक सार्वभौमिक सत्य है, कि देश में चाहे कोई भी आर्थिक प्रणाली कार्यशील क्यों न हो, अर्थव्यवस्था में एक केन्द्रीय प्रवृत्ति एवं एक निश्चित उद्देश्य सदैव विद्यमान रहता है, जिसके अन्तर्गत देश के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने की चेष्टा की जाती है।

विभिन्न अर्थशास्त्रीयों ने आर्थिक प्रणाली को भिन्न-भिन्न शब्दों में परिभाषित किया है, जिसमें मुख्य निम्नलिखित हैं:

(1) श्रीमती जॉन रॉबिन्सन (Mrs. Joan Robinson) के अनुसार, "किसी भी आर्थिक प्रणाली को नियमों के एक समूह की, इनके औचित्य को प्रमाणित करने के लिए एक विचारधारा की तथा व्यक्ति के विवेक की जिसके द्वारा उसे पूरा करने के लिए प्रयत्न कर सके, आवश्यकता होती है।

(2) ग्रॉसमैन (Grossman) ने आर्थिक पद्धति को परिभाषित करते हुए लिखा है: आर्थिकसंस्थाओं का समुच्चय जो किसी अर्थव्यवस्था का लक्षण होता है, उसकी आर्थिक पद्धति बनाता है।" संस्थाओं (Institutions) से ग्रासमैन का आशय प्रथाओं के समुच्चय, व्यावहारिक नियम एवं स्थापित क्रियाविधियों से है।

(3) मैनुअल गॉटलिब (Manual Gottlibe) के अनुसार, "आर्थिक प्रणाली मनुष्य के जटिल सम्बंधों के उन तरीकों का अध्ययन है जिसके द्वारा व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग किया जाता है।"